cannot say offhand; I think there have been certain cases where we have given some grant for items which may be produced in cottage industry.

Shri Ranga: Is any effort being made to co-ordinate the work with the Defence Science research section to see that so far as this year's allotment to the various Universities is concerned, a reorientation is made in order to help the Defence Ministry solve quite a number of its own research problems in addition to what they are doing by themselves?

Shri Humayun Kabir: I think I have already informed the House that a Steering committee has been set up in which the C.S.I.R., the Defence Science organisation, Defence Production and other interested organisations are represented and they look into it So far as these research schemes are concrned, they are longstanding programmes and they are continuing. We will, of course, see that there is no duplication or overlappling.

Shri Sham Lal Saraf: May I know the criteria fixed for recognising private institutions for being given grants and also recognising scholars for research work?

Shri Humayun Kabir: So far as scholarships are concerned, I think I have mentioned in this House that for any student who has the necessary aptitude and necessary interest, we shall try to find a scholarship for research if he is willing to carry on research. So far as organisations are concerned, we have generally taken the line that they are co-operative research associations which have been set up by the industries concerned. If individual private organisations come, the case is examined on merits.

Shri Sham Lal Saraf: Criteria?

Shri Humayun Kabir: The criterion is of course their capacity to carry on such work.

राज्य शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

\+

*६०३. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री म श्वर नायक :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० ना० विद्यालंकार :
श्री गो० महन्ती :
श्री राम चन्द्र मल्लिक :
श्री प्र० सिह० सहगल :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हुये राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई है कि शिक्षा प्रणाली में बार बार परिवर्तन न किये जायें ; और

(ख) क्या इस सम्मेलन में यह भी सिफारिश की गई है कि तीन भाषाई फार्मूले को जल्दबाजी में लागू नहीं किया जाना चाहिये ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) जी नहीं । किन्तु सम्मेलन ने यह सिफारिश की कि शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति में तब तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि सम्मेलन को पहले उस पर विचार करने का अवसर न मिल जाये ।

(ख) जी नहीं ।

[(a) No, Sir. But the conference recommended that no major change should be made in the national pattern of education until the Conference had first an opportunity of considering it.

(b) No, Sir.]

Shrimati Savitri Nigam: May I know whether any discussion was heeld regarding the three-language formula and whether any decision was reached or any special recom-

mendation was made by the Central Government?

Dr. K. L. Shrimali: The position with regard to the three-language formula is, it has been accepted in principle by the States. The Education Ministers' Conference has recommended that a standing committee or a small committee of Ministers might be appointed to ensure the implementation of this formula.

Shrimati Savitri Nigam: May I know whether the most important subject of the education of the handicapped was also discussed, in which the Education Ministers also need some education?

Dr. K. L. Shrimali: On some occasions it would be a good thing if the hon. Member forgets about the handicapped.

श्री म० ला० द्विवेदी : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने यह चाहा कि शिक्षा पद्धति के सिद्धांतों में परिवर्तन करने से पूर्व उन से परामर्श किया जाये । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार का कभी यह विचार रहा था कि बगैर उनके परामर्श के शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया जाये । यदि नहीं, तो यह बात क्यों उत्पन्न हुई ?

Dr. K. L. Shrimali: The hon. Member is aware that the States are free, as far as education is concerned, to have their own pattern. We have been trying to evolve a national pattern, and, therefore, it was thought necessary that some such step should be taken. I am glad to inform the House that the Education Ministers unanimously agreed that no further changes in the pattern should be made without prior consultation with the Education Ministers' Conference.

Shri Maheswar Naik: May I know whether Government have made any assessment of the extent of attainment of the objectives for which the three-language formula has been introduced in the different States?

Dr. K. L. Shrimali: No assessment is made. This question has been examined by various bodies, and it has been felt that it is in the national interest that our children should learn three languages.

Shri P. R. Chakraverti: While formulating the three-language formula, was there any condition that Hindi should be one of the three languages, and if not, why not?

Dr. K. L. Shrimali: In the three-language formula, Hindi is one of the subjects.

श्री द्वा० ना० तिवारी : जब यह सर्वसम्मत है और अक्सर यह बात कही जाती है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति देश की वर्तमान परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, तो फिर इस प्रश्न पर शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में क्यों नहीं विचार किया गया ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन के सामने यह प्रश्न आया था या नहीं कि वर्तमान शिक्षा पद्धति को बदल कर देश की वर्तमान परिस्थिति के मुताबिक एक शिक्षा पद्धति कायम की जाये ।

डा० का० ला० श्रीमाली : हिन्दुस्तान की आजादी के बाद शिक्षा पद्धति में काफी परिवर्तन हुआ है । प्रश्न यह था कि कोई एक राज्य उस पद्धति को न बदल दे, ताकि उसमें हेरफेर हो सके । इसलिये यह निश्चित किया गया था कि जब कभी कोई परिवर्तन का प्रश्न उठे, तो पहले कांफ्रेंस के सामने यह सवाल आना चाहिये । जहां तक माननीय सदस्य महोदय के प्रश्न का सवाल है, स्वतंत्रता के बाद इस बात की बराबर कोशिश की गई है कि हमारी शिक्षा पद्धति राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुकूल बराबर परिवर्तित होती रहे ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : शिक्षा मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई होगी—और संभवत: इस सम्मेलन में भी चर्चा का विषय बनी हो—कि राज्य सरकारों के द्वारा जितने भी विश्व-

विद्यालय चलाये जा रहे हैं, उन में राजनीतिज्ञों का अनुचित हस्तक्षेप हो रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों के इस शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में इस प्रकार की चर्चा भी आई थी कि विश्वविद्यालय की शिक्षा केन्द्रीय सरकार के संरक्षण में दी जाये ।

डा० का० ला० श्रीमाली : यह तो एक बड़ा प्रश्न है, जिस का उत्तर में आसानी से नहीं दे सकता हूं । माननीय सदस्य से मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक विश्वविद्यालयों का संबंध है, एक माडल लेजिस्लेशन कमेटी नियुक्त हुई है और उसकी रिपोर्ट जब आ जायेगी, तो वह राज्य सरकारों के पास भेज दी जायेगी ।

श्री कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि तीन-भाषायी फार्मूला कहां कहां लागू हुआ है ।

डा० का० ला० श्रीमाली : वह मद्रास के सिवाये लगभग सब स्टेट्स में कुछ हेरफेर के साथ लागू हो गया है ।

Educational Facilities to Students Joinnig Army

+

*604. Shri Bhakt Darshan:
Shri Yashpal Singh:
Shri Bishanchander Seth:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri M. S. Murti:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1020 on the 23rd January, 1963 and state:

(a) whether the Government of India has considered the matter of giving educational facilities to students joining army in consultation with the University Grants Commission;

(b) if so the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Education (Dr. K. L. Shrimali): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

(c) Does not arise.

STATEMENT

Pursuant to a note prepared in the Ministry of Education, the University Grants Commission considered the proposals made by various Universities with regard to facilities for students enlisting in the Armed Forces during the National Emergency and agreed that short of awarding degrees (without taking the university examinations), every facility should be provided to such students to complete their courses and take their examinations on their return.

2. With regard to any request for migration arising directly out of parents joining the Armed Forces, the Commission agreed that Universities be requested to give sympathetic consideration to deserving cases with a view to avoiding undue hardship.

3. Accordingly the Commission has requested the Vice-Chancellors of Indian Uniersities to consider this question if there is no objection and frame rules necessary for the purpose.

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण से मालूम होता है कि जो विद्यार्थी फौज में भर्ती हो जायेंगे, उनको बगैर परीक्षा दिये डिग्री प्राप्त करने की सुविधा नहीं दी जायेगी । लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है, पिछले महायुद्ध में यह सुविधा दी गई थी । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बार यह अन्तर क्यों किया जा रहा है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जहां तक मुझे मालूम है, पिछले महायुद्ध में भी डिग्री के लिये लड़कों को इम्तहान तो देना पड़ता था । इस बारे में सब विश्वविद्यालयों को युनिवर्स्टी ग्रांट्स कमिशन ने लिखा है और उन से कहा है कि जो लड़के आम कोर्सिस में भरती होते हैं, उनको सब तरह की सुविधायें दी जायें, अगर उन्होंने कोर्स पूरा नहीं किया तो